

TODAY WEATHER



DAY

32°

Hi

NIGHT

28°

Low

संक्षेप

यूपी में मौसम की आंख मिचौली, कहीं बूढ़ाबांदी तो कहीं चटख धूप, गोरखपुर में भारी बारिश के आसार

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में इस वक़्त मौसम के अजब-गजब रंग हैं। झमाझम बारिश के बाद मानसून की रफ़्तार धीमी पड़ती नज़र आ रही है। राज्य के अधिकांश हिस्सों में उमस भरी गर्मी का आलम है। कुछ जगहों पर हल्की बूढ़ाबांदी तो कहीं कुछ जिलों में भारी बारिश के आसार बने हैं। राजधानी लखनऊ में सुबह से ही चटख धूप खिली है। उमस के साथ गर्मी यहाँ आमजन को बेहाल करने लगी है। मौसम विभाग के मुताबिक बीते 24 घंटों में मानसून सामान्य रहा। पश्चिमी यूपी के कुछ जिलों में हल्की-फुल्की और पूर्वी के कुछ हिस्सों में तेज बारिश हुई। 13 जुलाई-सोमवार को भी पश्चिमी यूपी में गरज-चमक के साथ बूढ़ाबांदी के आसार हैं। जबकि पूर्वी यूपी के सात जिलों में भारी बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने गोरखपुर, देवरिया, संत कबीरनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर और बलरामपुर में भारी बारिश की संभावना जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। तराई के जनपद, बहराइच, लखीमपुर खीरी, श्रावस्ती, मऊ और बलिया में भी बादलों की गरज के साथ वज्रपात के साथ बारिश संभव है। मौसम विभाग ने बरेली, पीलीभीत, रामपुर, सीतापुर में भी गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना जताई है। जौनपुर, अयोध्या, सुल्तानपुर, गोंडा, बिजनौर, सहारनपुर समेत आसपास के इलाकों में बौछरें पड़ सकती हैं। मौसम विभाग के मुताबिक आगामी 16 जुलाई तक मानसून की यही स्थिति रहेगी। इस दौरान ताम्रपान में भी दो से चार डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। जाहिर है कि ऐसी स्थिति में गर्मी बढ़ेगी। बारिश के मौसम में उमस के साथ गर्मी थोड़ा तंग कर सकती है।

मानसून सत्र से पहले सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, विपक्ष के मुद्दों पर होगी चर्चा; 20 जुलाई से शुरू होगी संसद की कार्यवाही

नई दिल्ली, एजेंसी। संसद के मानसून सत्र की शुरुआत से एक दिन पहले केंद्र सरकार ने 19 जुलाई को सर्वदलीय बैठक बुलाने का फैसला किया है। इस बैठक में सरकार अपने विधायी एजेंडे की जानकारी सभी दलों के सामने रखेगी, जबकि विपक्षी पार्टियां सत्र के दौरान उठाए जाने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर अपनी रणनीति साझा करेंगी। संसद के प्रत्येक सत्र से पहले होने वाली यह परंपरागत सर्वदलीय बैठक 19 जुलाई को सुबह 11 बजे आयोजित की जाएगी। केंद्र सरकार के पास इस मानसून सत्र में कई महत्वपूर्ण विधेयक पेश करने की तैयारी है। ऐसे में बैठक के दौरान सरकार विपक्ष से सदन की कार्यवाही सुचारु रूप से चलाने के लिए सहयोग की अपील कर सकती है। इस बार संसद का मानसून सत्र राजनीतिक रूप से काफी गर्म रहने की संभावना जताई जा रही है। विपक्ष सरकार को कई मुद्दों पर धरने की तैयारी में है, वहीं हाल के दिनों में कई राजनीतिक दलों के भीतर हुए बदलावों का असर भी सदन की रणनीति पर दिखाई दे सकता है। विपक्षी दलों में टूट और आंतरिक विवादों के कारण संसद में समीकरण बदल गए हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में हार के बाद तृणमूल कांग्रेस (TMC) में भी अंदरूनी हलचल देखने को मिली है।

लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे का नितिन गडकरी, सीएम योगी और राजनाथ ने किया उद्घाटन

30 मिनट में पूरा होगा 63 KM का सफर

आर्यावर्त क्रांति व्यूरो

उन्नाव। उत्तर प्रदेश की महत्वाकांक्षी लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे परियोजना का सोमवार को औपचारिक लोकार्पण हो गया है। उन्नाव के पड़री स्थित झाऊखेड़ा रेस्ट एरिया में आयोजित कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। लोकार्पण के साथ ही यह हाईस्पीड एक्सप्रेसवे आम जनता के लिए खुल गया है।

इससे लखनऊ और कानपुर के बीच यात्रा अधिक तेज, सुरक्षित और



सुविधाजनक होगी। बता दें कि अभी ढाई से तीन घंटे लखनऊ से कानपुर सफर पूरा करने में लगते हैं, लेकिन एक्सप्रेसवे के खुलने के साथ ये सफर

महज 30 से 45 मिनट में पूरा होगा। लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे 63 किलोमीटर लंबा है।

उद्घाटन से पहले मुख्यमंत्री योगी

आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। कहा कि जब सड़कें बेहतर होती हैं, तब दूरी घटने के साथ-साथ विकास की गति बढ़ती है, निवेश के नए द्वार खुलते हैं और जनजीवन में नई संभावनाओं का संचार होता है। इसी विचार को नई गति देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के कर कमलों द्वारा आज 4,850 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से 3 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण/शिलान्यास होगा। ये परियोजनाएं उत्तर प्रदेश में आधुनिक अवसंरचना, सुगम

आवागमन और तीव्र आर्थिक प्रगति के नए अध्याय की आधारशिला सिद्ध होंगी।

कार्यक्रम के अनुसार, उन्नाव में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्सप्रेसवे का निरीक्षण करते हुए सड़क मार्ग से लखनऊ रवाना होंगे। इसके बाद सरोजनीनगर में आयोजित मुख्य समारोह में परियोजना का औपचारिक लोकार्पण किया जाएगा। इस दौरान तीनों नेता भाजपा पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचआई) के वरिष्ठ अधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे।

राम मंदिर में निकली सीईओ की नौकरी, 50 से 70 साल तक के लोग कर सकते हैं आवेदन

आर्यावर्त क्रांति

अयोध्या। श्री राम जन्मभूमि तीर्थक्षेत्र (न्यास) ने मंदिर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) के पद पर नौकरी निकाली है। यह एक कॉन्ट्रैक्ट आधारित नौकरी होगी। शुरुआत में तीन साल के लिए अनुबंध किया जाएगा। अच्छा काम रहने पर इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। न्यास की तरफ से साफ किया गया है कि सिर्फ 50 से 70 साल की उम्र के लोग ही आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने वाले व्यक्ति को हिंदी और अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान होना जरूरी है। 18 जुलाई को शाम 4 बजे तक आवेदन किए जा सकते हैं।

श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने सोमवार को सीईओ पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस पद पर चुना जाने वाला व्यक्ति अयोध्या में राम मंदिर का पहला सीईओ होगा। एक्स



पर एक पोस्ट में ट्रस्ट ने कहा कि योग्य उम्मीदवार श्री राम जन्मभूमि मंदिर के सीईओ पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें कहा गया है कि आवेदन 18 जुलाई शाम चार बजे तक स्वीकार किए जाएंगे। यह नियुक्ति महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मंदिर के चढ़ावे के कथित गवन की पृष्ठभूमि में की जा रही है।

रविवार को राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने कहा था कि पहले सीईओ की जिम्मेदारियां और शक्तियां ट्रस्ट द्वारा ही तय की जाएंगी और ट्रस्ट या सीईओ के कामकाज में कोई सरकारी हस्तक्षेप

नहीं होगा। उन्होंने कहा था कि सीईओ की प्राथमिक जिम्मेदारी ट्रस्ट में भक्तों के विश्वास को बनाए रखना होगा। सीईओ मंदिर की वित्तीय व्यवस्था की भी देखरेख करेंगे, यह सुनिश्चित करेंगे कि अयोध्या आने वाले भक्तों को आवश्यक सुविधाएं मिलें और इसके प्रति जवाबदेह रहते हुए ट्रस्ट के सहायक के रूप में कार्य करें। ट्रस्ट तय करेगा कि सीईओ को कितना अधिकार सौंपा जाए।

नृपेंद्र मिश्रा के अनुसार सीईओ कार्यालय के कामकाज के लिए आवश्यक कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिए स्वतंत्र होंगे, हालांकि समग्र प्रशासन ट्रस्ट के नियंत्रण में रहेगा। इस महीने की शुरुआत में ट्रस्ट ने आवेदनों की जांच करने और पद के लिए उपयुक्त उम्मीदवारों की सिफारिश करने के लिए एक तीन सदस्यीय समिति का गठन किया है।

बदरीनाथ धाम। बदरीनाथ धाम मंदिर में दान-चढ़ावा राशि में कथित गड़बड़ी के मामले में एक्शन शुरू हो गया है। उत्तराखंड पुलिस ने प्रमोद नौटियाल नाम के आरोपी कर्मचारी को देहरादून से गिरफ्तार किया है। पूछताछ के बीच पुलिस उसे बदरीनाथ लेकर पहुंच रही है। बदरीनाथ धाम में वित्तीय अनियमितता का मामला सामने आने के बाद से ही प्रमोद नौटियाल फरार चल रहा था। पुलिस ने उसे देहरादून से गिरफ्तार किया है। प्रमोद धाम से जुड़ा कर्मचारी है। अब पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। मामला काफी संवेदनशील है। इसलिए भी क्योंकि यूपी के अयोध्या स्थित राम मंदिर में चंदा-चढ़ावा चोरी पर भारी बवाल मचा है। आठ आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और तीन सदस्य ट्रस्ट से निकल गए। एसआईटी मामले की जांच कर रही है।

मोदी सरकार और प्रधान ने जवाबदेही से मुंह मोड़ा, अब शिक्षा में क्रांति का समय : राहुल गांधी



नई दिल्ली, एजेंसी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को कहा कि भारत की शिक्षा व्यवस्था अब 'बेईमान वसूली का तंत्र' बन गई है। उन्होंने कहा कि अब शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाने का समय आ गया है। राहुल गांधी ने 'छात्रों की गूंज' अभियान के तहत छात्रों से अपने दूसरे संवाद से पहले यह बात कही।

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर मोदी सरकार और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने चुप्पी साध ली है। उन्होंने कहा कि दोनों ने

जवाबदेही से मुंह मोड़ लिया है।

राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट की। इसमें उन्होंने लिखा, 'भ्रष्ट, अन्यायी, पक्षपाती, बेईमानी- ये चार शब्द मेरे नहीं, ये देश के छात्र आज भारत की शिक्षा व्यवस्था के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। सच यही है कि भारत की शिक्षा व्यवस्था अब एक बेईमान वसूली तंत्र बन चुकी है।'

कांग्रेस नेता ने क्या आरोप लगाए?

उन्होंने आगे कहा, "जो व्यवस्था बच्चों के भविष्य को तैयार करने के लिए बनी थी, वो आज उन्हें और उनके परिवार को कर्ज, तनाव और निराशा में धकेल रही है।" कांग्रेस नेता ने कहा, 'इसी भ्रष्टाचार ने पेपर लीक

माफिया को जन्म दिया, 'जो तैयारी कर रहे लाखों छात्रों की वर्षों की मेहनत एक झटके में लूट लेता है'।

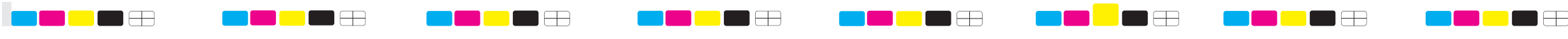
कांग्रेस नेता ने आगे कहा, 'यहां दोषी ठेकेदारों और अधिकारियों को ठेके और तस्करी मिलती है। लेकिन सजा किस मिलती है? उन छात्रों को, रहे हैं। सच यही है कि भारत की शिक्षा व्यवस्था अब एक बेईमान वसूली तंत्र बन चुकी है।'

कांग्रेस नेता ने आगे कहा, "जो व्यवस्था बच्चों के भविष्य को तैयार करने के लिए बनी थी, वो आज उन्हें और उनके परिवार को कर्ज, तनाव और निराशा में धकेल रही है।" कांग्रेस नेता ने कहा, 'इसी भ्रष्टाचार ने पेपर लीक

यूएनएससी की अस्थायी सदस्यता के लिए भारत करेगा दावेदारी, जयशंकर शुरू करेंगे अभियान

नई दिल्ली, एजेंसी। भारत आज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में 2028-29 के कार्यकाल के लिए गैर-स्थायी सदस्यता की अपनी दावेदारी का औपचारिक अभियान शुरू करेगा। विदेश मंत्री डॉ। एस। जयशंकर न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में #India4UNSC 2028-29: Peace, Planet, Progress अभियान की शुरुआत करेंगे। इस दौरान वो संयुक्त राष्ट्र महासचिव पंटोनियो गुटेरेस से भी मुलाकात करेंगे। भारत ऐसे समय यह अभियान शुरू कर रहा है जब दुनिया रूस-यूक्रेन युद्ध, गाजा संघर्ष और पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव जैसी कई चुनौतियों का सामना कर रही है। नई दिल्ली का प्रयास खुद को एक जिम्मेदार वैश्विक शक्ति और

विकासशील देशों यानी Global South की मजबूत आवाज के रूप में स्थापित करने का है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में 2027 में होने वाले चुनाव में भारत एशिया-प्रशांत समूह की एक सीट के लिए ताजिकिस्तान से मुकाबला करेगा। अगर भारत चुनाव जीतता है तो वो 2028-29 के कार्यकाल के लिए नौवीं बार सुरक्षा परिषद का गैर-स्थायी सदस्य बनेगा। भारत इससे पहले 1950-51, 1967-68, 1972-73, 1977-78, 1984-85, 1991-92, 2011-12 और 2021-22 में सुरक्षा परिषद का निर्वाचित सदस्य रह चुका है। 2010 में हुए चुनाव में भारत को 192 में से 187 वोट मिले थे, जो हाल के वर्षों में किसी भी उम्मीदवार के लिए सबसे मजबूत समर्थन में से एक था।



नक्सलवाद के बाद घुसपैठ पर निर्णायक प्रहार

देश को नक्सल आतंक की जकड़ से बाहर निकालने और जम्मू-कश्मीर तथा पूर्वोत्तर में आतंकवाद पर निर्णायक प्रहार के बाद अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय सुरक्षा के अगले चरण का बिगुल फूंक दिया है। इस बार निशाने पर केवल घुसपैठ नहीं, बल्कि घुसपैठ के जरिये सीमावर्ती इलाकों में बदलता जनसंख्या संतुलन, तस्करी, मादक पदार्थों का जाल, कट्टरपंथ, ड्रोन खतरें, संगठित अपराध और सीमा पार से संचालित छद्म युद्ध की पूरी रणनीति है। अमित शाह ने स्पष्ट संकेत दिया है कि देश को घुसपैठिया मुक्त बनाने और सीमाओं को अभेद्य सुरक्षा कवच देने का व्यापक अभियान अब सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। अमित शाह का मानना है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में अस्वाभाविक जनसंख्या परिवर्तन केवल स्थानीय समस्या नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों की राष्ट्रीय सुरक्षा, सामाजिक स्थिरता और सामरिक संतुलन से जुड़ा हुआ प्रश्न है, ऐसे में यह अभियान वर्तमान के साथ-साथ भविष्य के भारत की सुरक्षा का भी मजबूत आधार बनेगा। हम आपको बता दें कि नई दिल्ली में आयोजित सीमांत जिला पुलिस अधीक्षक सम्मेलन को संबोधित करते हुए अमित शाह ने सीमा सुरक्षा के लिए सरकार की नई और व्यापक रणनीति सामने रखी। उन्होंने कहा कि यह सम्मेलन सीमा सुरक्षा के समग्र दृष्टिकोण को संस्थागत स्वरूप देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अब केवल भूमि सीमाओं तक ही नहीं, बल्कि आने वाले समय में तटीय सीमाओं की सुरक्षा के लिए भी इसी प्रकार का समग्र और एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। सम्मेलन में सीमा सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों, उनके समाधान और भविष्य की नीति तैयार करने पर व्यापक विचार विमर्श किया गया। अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की सीमा सुरक्षा व्यवस्था अब केवल चौकियों और गश्त तक सीमित नहीं रहेगी। सरकार सीमा सुरक्षा बलों, राज्य सरकारों, जिला प्रशासन, केंद्र सरकार के संबंधित विभागों और सीमावर्ती क्षेत्रों के स्थानीय नागरिकों को साथ जोड़कर चार स्तरीय सुरक्षा तंत्र तैयार कर रही है। यही चतुष्कोणीय सुरक्षा व्यवस्था भविष्य में भारत की सीमाओं को अभेद्य बनाने का सबसे मजबूत आधार बनेगी। उन्होंने कहा कि सुरक्षित सीमा, समृद्ध सीमावर्ती क्षेत्र और सतर्क समाज मिलकर ही राष्ट्र की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। गृह मंत्री ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि भारत की लगभग पंद्रह हजार किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा अठारह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरती है। इतनी विशाल सीमा की सुरक्षा केवल सुरक्षा बलों के भरोसे संभव नहीं है। इसके लिए स्थानीय समाज की भागीदारी, प्रशासनिक समन्वय और आधुनिक तकनीक का प्रभावी उपयोग अनिवार्य है। इसी सोच के तहत सरकार अलग थलग सीमा चौकियों की पुनर्नी व्यवस्था से आगे बढ़कर एकीकृत सुरक्षा तंत्र विकसित कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत की स्मार्ट सीमा की परिकल्पना आने वाले वर्षों में दुनिया की सबसे आधुनिक सीमा सुरक्षा व्यवस्था का रूप लेगी। अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने नक्सलवाद, जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद और पूर्वोत्तर में हिंसा के खिलाफ उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। अब अगले तीन वर्षों में मादक पदार्थों के अवैध कारोबार पर भी निर्णायक प्रहार किया जाएगा। साथ ही ऐसा मजबूत सुरक्षा ढांचा तैयार किया जा रहा है जिससे देश पूरी तरह घुसपैठ मुक्त बने और भविष्य में किसी भी प्रकार की अवैध घुसपैठ की संभावना लगभग समाप्त हो जाए। उन्होंने कहा कि पहले समस्याएं स्थायी होती थीं और समाधान अस्थायी, लेकिन अब सरकार समस्याओं की जड़ पर प्रहार कर स्थायी समाधान तैयार कर रही है। देखा जाये तो इस पूरी रणनीति का सबसे महत्वपूर्ण पहलू सीमावर्ती क्षेत्रों में बदलते जनसंख्या स्वरूप पर मोदी सरकार का विशेष ध्यान है। अमित शाह ने स्पष्ट कहा कि सीमावर्ती इलाकों में अस्वाभाविक जनसंख्या परिवर्तन का सबसे बड़ा कारण अवैध घुसपैठ है। इसी कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसंख्या अध्ययन अभियान प्रारंभ किया है, जिसके तहत जनसंख्या में हो रहे अस्वाभाविक बदलावों का अध्ययन किया जाएगा, उनके कारणों की पहचान होगी और भविष्य में ऐसे परिवर्तनों को रोकने के उपाय सुझाए जाएंगे। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि अस्वाभाविक कारणों से होने वाली जनसंख्या वृद्धि पर कठोरता के साथ नियंत्रण किया जाएगा। गृह मंत्री ने निर्देश दिया कि सीमावर्ती क्षेत्रों में जनसंख्या परिवर्तन से जुड़ी हर महत्वपूर्ण सूचना सबसे निचले स्तर से लेकर शीर्ष स्तर तक तत्काल पहुंचनी चाहिए, ताकि समय रहते आवश्यक कार्रवाई की जा सके। सरकार सीमाओं को मजबूत बनाने के लिए आधारभूत ढांचे पर भी अभूतपूर्व निवेश कर रही है। अमित शाह ने बताया कि सीमा क्षेत्रों में आधारभूत संरचना पर निवेश में चार सौ प्रतिशत की वृद्धि की गई है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ सड़कों, संचार व्यवस्था, निगरानी तंत्र तथा अन्य सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है।

कौशल बने उम्मीदवार की पहली पहचान न कि कोई उपाधि



निशा सिंह

ऐसा नहीं

लगता कि यह

किसी एक

नियोक्ता की

बात है। यह

भर्ती प्रक्रिया की

बुनावट में ही

बसी एक आदत

है

किसी उम्मीदवार की पहली पहचान उसका कौशल होना चाहिए, न कि उसका संबोधन या उपाधि। भारत के बदलते नौकरी बाजार पर एक लेख के लिए भर्ती प्रक्रियाओं पर शोध करते समय हाल ही में कुछ ऐसा देखने को मिला, जिसने रुक कर सोचने पर मजबूर कर दिया। कई भर्ती प्लेटफॉर्म उम्मीदवारों से उनका संबोधन, लिंग, वैवाहिक स्थिति, यहाँ तक कि यौन रूझान तक पूछ लेते हैं, जबकि उनके अनुभव की एक पंक्ति भी अभी तक पढ़ी नहीं गई होती।

कापॉरेट कम्युनिकेशन एक्सपर्ट निशा सिंह का कहना है कि यह महज़ एक धारणा नहीं है। इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के एक आर्थिक सम्मेलन में प्रस्तुत भारत के एचआर भर्ती बाजार पर हुए एक क्षेत्रीय प्रयोग में, समान योग्यता वाले आवेदन भेजे गए जिनमें केवल घोषित वैवाहिक स्थिति अलग थी। फिर भी भर्तीकर्ताओं की प्रतिक्रिया अलग-अलग रही। इसके अलावा, 2024 की एक रॉयटर्स जांच में सामने आया कि भारत में फॉक्सकॉन के लिए काम करने वाली भर्ती एजेंसियाँ विवाहित महिलाओं को असेंबली-लाइन की नौकरियों से बाहर कर रही थीं, एक प्रथा, जिसे कंपनी ने सामने आने के बाद सुधारने की बात कही। साक्षात्कार के स्तर पर भी तस्वीर अलग नहीं है। फेमिनिज्म इन इंडिया में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, 42 प्रतिशत महिला उम्मीदवारों से कम से कम एक व्यक्तिगत सवाल पूछा गया, जबकि पुरुष उम्मीदवारों के मामले में यह आंकड़ा 33 प्रतिशत था, जिनमें वैवाहिक स्थिति और पारिवारिक पृष्ठभूमि सबसे आम रहे।

ऐसा नहीं लगता कि यह किसी एक नियोक्ता की बात है। यह भर्ती प्रक्रिया की बुनावट में ही बसी एक आदत है, फॉर्म और साक्षात्कार की संक्रिप्त, जो यह पूछने से पहले कि कोई क्या कर सकता है, यह पूछ लेते हैं कि वह कौन है। इस क्रम को पलटने के पक्ष में तर्क लगातार मजबूत होते जा रहे हैं। मैकिंज़ी के शोध के अनुसार, कौशल के आधार पर की गई भर्ती, शिक्षा या पृष्ठभूमि के आधार पर की गई भर्ती की तुलना में कार्यक्षमता का कहीं अधिक भरोसेमंद संकेत देती है। लिंकडइन की इंडिया फ्यूचर ऑफ़ रिक्रूटिंग रिपोर्ट के अनुसार, चार में से तीन भर्ती कर्ता पहले ही मानते हैं कि भविष्य कौशल-आधारित भर्ती का है। भारत के अपने श्रम आँकड़े भी इस बात को



और वजन देते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2025–26 के अनुसार महिला श्रम बल भागीदारी दर 2017–18 के 23.3 प्रतिशत से बढ़कर 2023–24 में 41.7 प्रतिशत हो गई। यह वास्तविक प्रगति है। लेकिन ऐसी प्रगति, जो अब भी भर्ती के पहले ही चरण में उन फॉर्मों से आकार लेती है, जो योग्यता से पहले वैवाहिक स्थिति पूछते हैं।

क्या हो, अगर किसी भर्ती फॉर्म में सबसे पहला सवाल बस इतना हो- यह व्यक्ति क्या कर सकता है? इसने अब तक क्या बनाया है? इसने किन समस्याओं को सुलझाया है? और यह संगठन को क्या मूल्य दे सकता है? संबोधन, वैवाहिक स्थिति, लिंग, यौन रूझान, यह सब बाद में पूछा जा सकता है और वह भी सिर्फ तब, जब किसी भूमिका के लिए वाकई जरूरी हो, मूल्यांकन की प्रक्रिया से पूरी तरह अलग रखकर।

निशा सिंह का कहना है कि अधिकतर नौकरियों के लिए ये पहचान से जुड़े कॉलम किसी की क्षमता आंकने में कोई मदद नहीं करते। ये सिर्फ परंपरा के चलते बने रहते हैं, जरूरत के

कारण नहीं। बिना सवाल किए चली आ रही परंपरा, धीरे-धीरे पूर्वाग्रह में बदल जाती है। भारत तकनीक और नए क्षेत्रों से बदलती अर्थव्यवस्था के लिए एक भविष्य के लिए तैयार, कौशल-केंद्रित कार्यबल चाहता है। इस लक्ष्य के लिए सिर्फ पाठ्यक्रम सुधार और प्रशिक्षण ढाँचा काफी नहीं है, इसके लिए भर्ती प्रणाली को भी उसी सोच के अनुरूप बनाना होगा। कोई भी देश योग्यता पर आधारित होने का दावा नहीं कर सकता, जब तक उसके भर्ती फॉर्म यह पूछते रहें कि व्यक्ति कौन है, इससे पहले कि ये यह पूछें कि वह क्या योगदान दे सकता है। यह एक छोटी-सी, लेकिन आसानी से सुधारी जा सकने वाली बात है। नियोक्ता और भर्ती प्लेटफॉर्म बस अपने आवेदन फॉर्मों का क्रम बदल सकते हैं-पहले कौशल और अनुभव, बाद में पहचान से जुड़ी जानकारी और वह भी सिर्फ वहाँ, जहाँ वाकई जरूरी हो क्योंकि प्रतिभा की कोई उपाधि नहीं होती। क्षमता की कोई वैवाहिक स्थिति नहीं होती। हमारी भर्ती प्रणालियों को यह बात पहले से ही समझनी चाहिए।

ब्लॉग

आ गया मानसून

डॉ. सुधीर सक्सेना

आ गया मानसून। मानसून आ गया है। करीब एक पखवाड़े की लुकाछिपी के बाद अंततः मानसून आ गया। इतहाते-इतलाते मेघ पाहुने आखिरकार ताल-नखरे के साथ प्रकट हुए। धरती पुलक से भीग गई। यह अनहोनी नहीं है। यह सदियों से चला आया चक्र है। अनहोनी तब होती है, जब चक्र खँडित होता है और बादल रूठ जाते हैं, धरती की त्वचा में पपड़ियाँ पड़ जाती हैं और जीव-जंतु तुपात और व्यग्र हो जाते हैं। बहरहाल, किंचित विलंब ही सही, धरती और धरती के प्राणियों की प्रतीक्षा के मोद से भरे बादल आए, बरसे और कृतकृत्य हुए।

किसी ने कहा, 'अहा, बारिश आ गई। अंग्रेजीदाँ बोले, 'इट्स रेनिंग। मेरे जर्मन-भाषी मित्र ने दूरभाष पर कहा, 'एस रेनैट। तो मराठी माणूस चहका, 'पाऊस आला। कोकणस्थ ने भी कहा, 'हओ, पाउस आला। मेरी बंगालन सखी ने आसमान से हुई रस-वृष्टि में आपादमस्तक भीग जाने के बाद संदेशा भेजा, 'वृष्टि एलो। फोन की घंटी घनघनाई! मस्क्वा से मेरे मित्र का प्रश्न था, 'प्रिष्योल दोशद? मैंने सानंद कहा—'दा। दोस्त मेरे आनंद में शरीक हुआ।

मानसून आता है, तो लोगबाग खुश होते हैं। मानसून हमारा शब्द नहीं है, अलबत्ता अब पूरे मुल्क में चलन में है। हम भारतीयों ने इसे हृदय से अपना लिया है। यह हमारी सहृदयता का सरस प्रमाण है। अब यह पराया या अजनबी नहीं रहा। अरबी मूल का यह शब्द ब्रिटिश इंडिया में चलन में आया। बीती सदी के शुरू में लार्ड कर्जन ने कहा था कि इंडिया में फसल मानसून की बिसात पर खेला जाने वाला जुआ है। लार्ड कर्जन गए, उनके सजातीय गए, लेकिन मानसून का इंतजार तब भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। यह मानसून की सनातन महत्ता है। वर्षा द्वैत के अद्वैत और अद्वैत के द्वैत में परिवर्तन का दश4न है। मानसून का आना इंतजार की घड़ियों का खत्म होना है। मानसून प्रतीक्षा के उपरांत मिलन के पर्याय का घोटक है। यह अनिर्वचनीय आनंद की मंगल-वेला है।

खानखाना कहते हैं—

दादुर, मोर, किसान मन, लग्यो रहै घन माहिं।
रहिमन चातक रटनि हूँ, सरवर को कोउ नाहिं॥

विज्ञान इसकी पुष्टि करता है कि मेंडक वर्षा ऋतु आने पर परम प्रसन्न होते हैं। पावस के आने पर मोर का नृत्य उनके उल्लास का परिचायक है। और किसान? वर्षा उसके लिए सर्वस्व है। वह उसी से निहाल होता है। एक और जीव है, जिसका पावस से विचित्र नाता है। वह है चातक। हिन्दी और संस्कृत वाङ्मय में चातक का जिज्ञा अनगिनत बार हुआ है।

मानसून का क्या अभिप्राय है? अरबी में मौसिम मौसम के लिये प्रयुक्त होता है। पुर्तगाली में



यही मान्साओ है और डच भाषा में मॉनसन।

सागर से जमीन की ओर प्रवाहित नम हवाओं के लिये प्रयुक्त यह शब्द अब हमारा प्रिय और व्यवहत शब्द है। दिशाएँ ऋतुनिष्ठ होती हैं। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से आने वाली गीली हवा वर्षा का निमित्त बनती है। जलागारों या स्रोतों से वाष्पीकृत बूँदें वाष्परूप में नहीं रहना चाहतीं, वे द्रवीभूत होना चाहती हैं। उनकी इसी नैसर्गिक चाहत की परिणति है वर्षा।

सौभाग्य देखिये कि भारत में अनुमानतः तीन-चार माह वर्षा होती है, किन्तु विश्व में सर्वाधिक वर्षा का कीर्तिमान भारत के नाम दर्ज है। चेरापूँजी को कौन नहीं जानता? सन 1860-61 में 26971 मि.मी. वर्षा से विश्व-कीर्तिमान स्थापित कर चुके चेरापूँजी को पूर्वी खासी पहाड़ियों में स्थित मर्वसिनराम ने इस गौरव से अपदस्थ कर दिया है। कुशीनुमा पहाड़ियों में स्थित मर्वसिनराम में ढाई सौ से तीन सौ दिन सालाना औसतन 467 इंच बारिश होती है। चेरापूँजी और मर्वसिनराम दोनों ही मेघालय में स्थित हैं। दुनिया में अटकामा सबसे कम वर्षा का इलाका है, तो मेघालय अधिक वर्षा के मामले में अग्रणी। मेघ मेघालय में धारासार नहीं बरसने तो और कहाँ बरसेगे?

भारत 80 प्रतिशत से अधिक वर्षा के लिये मानसून का शुक्रगुजार है। मानसून की कृपा है तो भारत में श्री, सुषमा, अन्न-भंडार और सुख-चैन की व्याप्ति है।

भारत में साहित्य, कला और संस्कृति ऋतुओं से जुड़ी हुई हैं। वाल्मीकि-कालिदास से लेकर आधुनिक काल में नागार्जुन तक काव्य-रचना के लिये वर्षा से प्रेरित हुए। वैदिक ऋषि ने पर्जन्य को पिता के रूप में अभ्यर्थना की। आदिकवि वाल्मीकि

ने मेघमाला को ऐसी सीढ़ी कहा, जिस पर चढ़कर कुटज और अर्जुन की माला से सूर्य की आराधना कर सकते हैं- 'रामायण में वह लिखते हैं-

रजः प्रशान्तः स हिमोद्यवायुः, निदाघदोषः

प्रसरः प्रशान्तः।

स्थिता हि यात्रा वसुधाधिपानां, प्रवासिनां च स्वदेशगमनम्॥

उन्होंने वर्षाजन्य स्थितियों का क्या ही सुंदर वर्णन किया। कविकुलगुरु कालिदास की तो कृति ही 'मेघदूत' है। 'ऋतुसंहार' में उन्हें वर्षा का आगमन ऐसा प्रतीत होता है, मानो पावस जल से भरे बादलों के मतवाले हाथी पर बैदली, विद्युत्-पताका थामे, मेघों की गर्जना का मृदंग बजाते, राजाओं की भाँति ठाठ-बाट से आ गया हो।

कालिदास के यक्ष और अमरूक-शतक की नायिका की आशा का केन्द्र कोई और नहीं, बादल ही हैं। शूद्रक, भवभूति और जयदेव ने भी मेघों का बखान किया है। आधुनिक युग में निराला 'अति घिर आए घन पावस के' लिखते हैं, महादेवी वर्मा कहती हैं—'मैं नीर भरी दुःख की बैदली।'

माखनलाल चतुर्वेदी लिखते हैं- बदरिया थम-थम कर झर रो!

सागर को मत भरे आभागन,

गागर को भर रो!

नागार्जुन भी अमूल धवल गिरि के शिखरों पर बादल को धिरेते देखते हैं। वीरेंद्र मिश्र कजरी को स्वर देने और वाणी को पानी का वर देने को बादल की अर्चना करते हैं। नजीर अकबराबादी बादलों को काव्य के अनुशासन में बांधते हैं। पंडित छन्नूलाल मिश्र गाते हैं?

सावन झर लागे ला धीरे-धीरे..

अकेली डर लागे ला धीरे धीरे। जब वह गाते

है तो याद आती है तुलसी की पंक्तियां : घन घमंड नभ गरजत घोरा। प्रिया हीन डरपत मन मोरा। पावस में मेरा कवि मन कहता है- साथ जब होती हो तुम /चाहते चाहते हैं बस/ कि दूर- दूर तलक/ न सायबान हो/ न दरख्त / न ओट/ न छज्जा/ बस, गजब की बारिश हो/ भीगते रहे हम आपादमस्तक/एक साथ सदियों तक।

सुनिये, पं. हृदयनाथ मंगेशकर का मराठी गीत - तो गेली तेव्हा रिमझीम पाऊस निनादत होता। मेघात मिसळली किरणे, हा सूर्य सोडवित होता। आप सुरों की बारिश में भीग जआगे।

यासिन कमाल की शुरू कीदो पंक्तियाँ हैं - बूँदे झर रही हैं, बारिश में भीगने का सुख ही अलग है। प्रिया के साथ भीगने का सुख ही अलग है। सर्वथा अनिर्वचनीय।

भारतीय फिल्मों में बारिश की बूँदें खूब भरी हैं और वर्षा के अनगिन दृश्य उभरे हैं। याद कीजिये प्यार हुआ, इकरार हुआ गीत या फिर इक लड़की भीगी भागी सी या ओ, सजना बर?खा बहार आयी। ये सन 1960 के आसपास की फिल्में हैं जिनदी भर नहीं भुलेंगी वो बरसात की रात भी तभी का है। रिमझिम गिरे सावन, आज रपट जाये, लगी आज सावन की, टिप-टिप बरसा पानी, अबके सावन, बरसी रे मेघा बाद के है।

वर्षा- गीतों का यह श्रुति मधुर क्रम जारी रहेगा। आरती मुखर्जी का गाया बंगला गीत 'वृष्टि, वृष्टि, वृष्टि! ए कोनो अपरूप सृष्टि!'/एतो मिष्टि मिष्टि मिष्टि, आमार हरिये गेले दृष्टि। मैंने लेखिका - गायिका अमृता बेरा के मुख से सुना और मंत्रमुग्ध हुआ। मराठी भी कहीं पोछे है! गारवा (मिलिंद इंगळे), 'चिंव भिजलेले (शंकर महादेवन) या श्रावणमासी (स्वप्निल बांदोडकर) को सुनिये। या फिर सुनिये बालगीत' ये रे ये रे पावसा तुला देतो पैसा पैसा/ पैसा झाला खोटा/ पाऊस आला मोठा। ये गीत आपको भीतर तक भीगे देंगे।

आप हैव यू एवर सोन द रेन अथवा रिदम ऑफ द रेन सुनिये या फिर पर्पल रेन या अंब्रेला। आप सुरों की बारिश में भीगेगे और चाहेंगे कि भीगते रहे।

निश्चित ही वर्षा एक अनूठा सुख है; काशुष भी, ऐंद्रिक भी। भाषणें और संगीत सुरू- ताल उसे व्यक्त करने का माध्यम। मानसून हमारा अतिथि है। हम उसके आने की तिथि की आतुर प्रतीक्षा करते हैं। हम अच्छे आतिथेय हों। उसकी अगवानी और अभ्यर्थन करें। हम धरती पर अटकामा होने से डरें। कोई पूछे : हैव यू सोन द रेन तो हमारा उत्तर स्वीकार में हो। हम वर्षा को भरबांह भेंटें। पावस भी कविता है। प्रकृति की अत्यंत सुंदर कविता। मानसून कितने भी दिनों के लिये क्यों न आये हम भूलें नहीं कि मानसून में जल नहीं, नेह बरसता है, आविरल-अविराम।



समस्या यह धारणा है कि परीक्षा तंत्र अकुशलता और भ्रष्टाचार के ग्रस्त है। इससे छात्रों का भविष्य अंधकारमय हुआ है। परीक्षा केंद्रों की 'बंकर' में तब्दील करने से यह धारणा दूर नहीं होगी।

पेपर लीक के बाद दोबारा हुए नेशनल एलिजबिलिटी- कम- एंट्रेस टेस्ट (स्नातक पूर्व) के लिए देश में बने 5,440 परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा का ऐसा घेरा खड़ा किया गया (अथवा ऐसा करने का प्रचार किया गया), मानों उन केंद्रों को किसी बड़े आतंकवादी हमले से बचाने की चुनौती सामने हो! परीक्षा आयोजन में वायु सेना, केंद्रीय सशस्त्र बलों, डाक विभाग, केंद्र सरकार के वित्तीय सेवा विभाग, और नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर की मदद ली गई। अंत में यह खबर भी आ गई कि नीट परीक्षार्थियों को असुविधा से बचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली हवाई अड्डे पर 45 मिनट तक इंतजार किया! यह दीर्घ बात है कि इन बड़ी सुखियों से पेपर लीक और परीक्षा संचालन व्यवस्था की पोल को ढका नहीं जा सका है।

छात्रों का टीवी रिपोटर्स से यह कहना अविश्वাস के गहराते माहौल को जाहिर कर देता है कि दोबारा परीक्षा में शामिल होने को लेकर वे उतने नर्वस नहीं हुए, जितनी इस आशंका से है कि कहीं फिर पेपर लीक ना हो जाए! वैसे दोबारा परीक्षा की दहशत से भी दर्शन भर से अधिक छात्र नर्वस हुए, जिनकी आत्महत्या की खबरें हाल में चर्चित रही हैं। ऐसी घटनाओं ने नौजवानों के एक बड़े वर्गों में आक्रोश भरा है। उसका नजारा फिलहाल दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के अनिश्चितकालीन विरोध प्रदर्शन में देखने को मिल रहा है। गुस्सा इसको लेकर है कि वर्तमान सरकार के तहत जवाबदेही की अवधारणा ही दफना दी गई है। कुछ भी हो जाए, उसके लिए कोई उत्तरदायी नहीं होता! गंभीर से गंभीर समस्या में सरकार के पास दो ही जवाब होते हैं: 'सिक््युरिटी स्टेट' के रूप में अपनी क्षमता का प्रदर्शन और धुआंधार प्रचार से अपने पक्ष में नैरेटिव खड़ा करना। नीट के दोबारा आयोजन में इन दोनों उपायों का खुल कर मुजाहिदा किया गया। लेकिन इन उपायों से समस्याएं दूर नहीं होतीं। समस्या बनी यह धारणा है कि परीक्षा का सरकारी तंत्र अकुशलता और भ्रष्टाचार के ग्रस्त है। इससे करोड़ों छात्र- नौजवानों का भविष्य अंधकारमय हो रहा है। परीक्षा केंद्रों की 'बंकर' में तब्दील करने से यह धारणा दूर नहीं होगी।

अब आप नहीं, आपका एआई करेगा यूपीआई पेमेंट ! जानिए क्या है ‘ यूनीफाइड एजेंट प्रोटोकॉल ’ और कैसे बदलेगा जेब का गणित

NPCI एक यूनिफाइड एजेंट प्रोटोकॉल (UAP) विकसित कर रहा है। UAP को एक भरोसेमंद, सामान्य और इंटरऑपरेबल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए डिजाइन किया जा रहा है। इसके जरिए एआई एजेंट को यूपीआई इकोसिस्टम में ट्रांजैक्शन करने के लिए रजिस्टर, वेरिफाई और ऑथराइज्ड किया जा सकेगा, और इसके लिए पेमेंट सिस्टम के मौजूदा इंफ्रा में कोई बदलाव नहीं करना पड़ेगा।



किसी सोचिए कि आप अपने एआई असिस्टेंट से अगले मंगलवार के लिए मुंबई-दिल्ली फ्लाइट बुक करने के लिए कहते हैं, और वह सिर्फ आपको ऑप्शन नहीं दिखाता-बल्कि खुद सबसे अच्छा ऑप्शन चुनता है, आपकी डिटल्स भरता है और पेमेंट भी कर देता है। खास बात तो ये है कि यह सब बिना आपके कुछ किए, बस आपके कहने पर हो जाता है।

आज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) एजेंट फ्लाइट बुक करने या ऑनलाइन शॉपिंग जैसे कामों के लिए ऑप्शन खोज सकते हैं, उनकी तुलना कर सकते हैं और सुझाव दे सकते हैं। लेकिन जब यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफ़ेस (यूपीआई) के जरिए पेमेंट करने की बात आती है, तो यह प्रोसेस रुक जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सिर्फ यूजर और रजिस्टर्ड पेमेंट ऐप्स ही यूपीआई ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, एआई एजेंट नहीं।

अगले कुछ समय के बाद आपको ऐसा होता हुआ दिखाई दे सकता है। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ऐसे ही एक सिस्टम पर काम कर रहा है, जिसका नाम Unified Agent Protocol है। इस सिस्टम के तहत एआई के थ्रू ही आपका पेमेंट होगा। ना तो इसके लिए क्यूआर कोड की जरूरत होगी, ना

तरह के पिन की। आइए इसके बारे में विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं...

एआई आज सीधे पेमेंट क्यों नहीं कर सकता?

UPI में ऑटो-पे (AutoPay) और रिजर्व पे (Reserve Pay) जैसे फीचर हैं, जो यूजर्स को खर्च की सीमा तय करके और एक बार अपने UPI पिन से ऑथेंटिकेट करके बार-बार होने वाले या भविष्य में होने वाले पेमेंट को परमीशन की सुविधा प्रोवाइड कराते हैं। इनका इस्तेमाल आमतौर पर नेटफ्लिक्स जैसी सब्सक्रिप्शन सर्विसेज या पहले से मंजूर किए गए अन्य ट्रांजैक्शन के लिए किया जाता है। लेकिन यह एआई एजेंट को स्वतंत्र रूप से खरीदारी के फैसले लेने और यूजर की ओर से पेमेंट करने की अनुमति देने जैसा नहीं है। इस अंतर को पाटने के लिए, खबर है कि NPCI एक यूनिफाइड एजेंट प्रोटोकॉल (UAP) विकसित कर रहा है। यह UPI इकोसिस्टम के भीतर AI एजेंट को वेरिफाई और ऑथराइज्ड करने के लिए एक प्रस्तावित फ्रेमवर्क है।

UAP से कैसा आ सकता है बदलाव?

बिज़नेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के अनुसार,

UAP को एक भरोसेमंद, सामान्य और इंटरऑपरेबल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए डिजाइन किया जा रहा है। इसके जरिए एआई एजेंट को यूपीआई इकोसिस्टम में ट्रांजैक्शन करने के लिए रजिस्टर, वेरिफाई और ऑथराइज्ड किया जा सकेगा, और इसके लिए पेमेंट सिस्टम के मौजूदा इंफ्रा में कोई बदलाव नहीं करना पड़ेगा।

UAP, यूपीआई की जगह नहीं लेगा। इसके बजाय, यह मौजूदा सिस्टम के ऊपर एक वेरिफिकेशन लेयर के तौर पर काम करेगा, जिससे भरोसेमंद एआई एजेंट मौजूदा पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाए रखते हुए सुरक्षित रूप सेयूपीआई के साथ इंटरैक्ट कर सकेंगे। अगर इसे लागू किया जाता है, तो UAP पेमेंट इकोसिस्टम को यह वेरिफाई करने का तरीका देगा कि ट्रांजैक्शन प्रोसेस होने से पहले एआई एजेंट यूजर की सहमति से काम कर रहा है।

यह कैसे काम कर सकता है?

हालाँकि इसके काम करने के तरीके के बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है, लेकिन उम्मीद है कि UAP मौजूदा यूपीआई इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करेगा। पेमेंट का तरीका कुछ ऐसा हो सकता है:

यूजर इंस्ट्रक्शन देगा→एआईअसिस्टेंट ऑप्शंस को कंपेयर करेगा, उसके बाद सबसे अच्छा ऑप्शन चुनेगा और पेमेंट रिवेस्ट जेनरेट करेगा। उसके बाद UAP यह वेरिफाई करेगा कि AI एजेंट रजिस्टर्ड है, भरोसेमंद है और यूजर की ओर से काम करने के लिए ऑथराइज्ड है। रिवेस्ट यूपीआई के जरिए भेजा जाएगा, यूजर या तो ट्रांजैक्शन को मंजूरी देगा है, या तय सीमा के अंदर पहले से मंजूर पेमेंट के मामलों में, लागू नियमों के आधार पर पेमेंट अपने-आप पूरा हो जाएगा।

क्या एआई को आपके पैसे का पूरा एक्सेस मिल जाएगा?

नहीं, जरूरी नहीं। हालाँकि फाइनल फ्रेमवर्क की घोषणा अभी बाकी है, लेकिन

उम्मीद है कि यह सिस्टम मौजूदा यूपीआई सर्विसेज जैसे ऑटोपे (AutoPay) और रिजर्व पे (Reserve Pay) की तरह काम करेगा, जहां यूजर अपने बैंक अकाउंट का अनलिमिटेड एक्सेस देने के बजाय खर्च की सीमा को पहले से मंजूर करते हैं।

पहले की मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, प्रस्तावित प्रोटोकॉल से यह वेरिफाई होने की उम्मीद है कि क्या कोई AI एजेंट यूजर की ओर से काम करने के लिए ऑथराइज्ड है, उस अधिकार की सीमा तय की जाएगी, और अगर उन सीमाओं का उल्लंघन होता है तो जवाबदेही तय की जाएगी। हालाँकि, अंतिम सुरक्षा उपाय इस बात पर निर्भर करेगे कि NPCI और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) फ्रेमवर्क को कैसे डिजाइन करते हैं। UAP को लॉन्च करने से पहले NPCI को RBI की मंजूरी की भी जरूरत होगी।

क्या गड़बड़ हो सकती है?

जैसे-जैसे पेमेंट सिस्टम एआई एजेंटों को शामिल करने के लिए विकसित हो रहे हैं, वैसे-वैसे साइबर अपराधी और फ्रॉड करने वाले भी उनका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। एआई असिस्टेंट को यूजर की ओर से परचेज करने की परमिशन देने से सेप्टी और कंज्यूमर प्रोटेक्शन से जुड़ी नई चुनौतियां पैदा होती हैं।हालाँकि यह तकनीक अभी शुरूआती दौर में है, लेकिन यह नए रिस्क भी लेकर आती हैं।

यह क्यों जरूरी है?

अगर इसे लागू किया जाता है, तो UAP भारत को एजेंटिक पेमेंट (एजेंट के जरिए होने वाले पेमेंट) के लिए नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने वाले शुरुआती देशों में शामिल कर सकता है। यह यूपीआई को एक ऐसे पेमेंट सिस्टम से बदलकर, जिसे यूजर मैनुअल रूप से चलाते हैं, एक ऐसे सिस्टम में बदल सकता है जिसका इस्तेमाल भरोसेमंद एआई एजेंट उनकी ओर से कर सकें।

पाकिस्तान में सेना बनाम सियासत : 'राजनीति करनी है तो वर्दी उतारें'

इस्लामाबाद, एजेंसी। पाकिस्तान के सबसे प्रभावशाली धार्मिक और राजनीतिक नेताओं में से एक मौलाना फजलुर रहमान का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वे देश के सैन्य प्रतिष्ठान पर तीखा हमला करते दिख रहे हैं। ने सेना पर संवैधानिक भूमिका का उल्लंघन करने, राजनीति में हस्तक्षेप करने और हिंसाग्रस्त बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में राज्य का शासन बहाल करने में विफल होने का आरोप लगाया।

पंजाब के कसूर में एक रैली को संबोधित करते हुए जमीयत उ ले मा - ए - इ स् लाम - फ ज ल (जेयूआई-एफ) के प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि सेना को अपनी संवैधानिक सीमाओं के भीतर रहना चाहिए। अगर वह राजनीतिक भूमिका निभाना चाहती है तो उसे चुनाव लड़ना चाहिए। उन्होंने कहा,

'अगर आप राजनीति करना चाहते हैं, तो वर्दी उतारकर आएं। चुनावों में भाग लें। इससे यह साफ हो जाएगा कि लोग वर्दीधारी लोगों को कितने वोट देते हैं।'

मौलाना फजलुर रहमान ने क्या दावा किया?

फजलुर रहमान ने पाकिस्तान की सुरक्षा स्थिति को लेकर दावा किया कि हिंसा के परतून-बहुसंख्यक क्षेत्रों में भी फैलने से पहले राज्य ने बलूचिस्तान के बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण लगातार खो दिया था। उन्होंने पूछा ' देश विखर रहा है। शासक कहाँ हैं?' 'बलूच क्षेत्रों में विद्रोह हुए थे। पूरा बलूच क्षेत्र पाकिस्तान के नियंत्रण से बाहर हो गया था। आज भी वहां पाकिस्तानी सरकार का कोई शासन नहीं है।' उन्होंने दावा किया कि बिगड़ती सुरक्षा स्थिति अब खैबर

पख्तूनख्वा तक फैल गई है।

फजलुर रहमान की टिप्पणियों का कारण क्या था?

यह तीखी आलोचना पाकिस्तान सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ओर से नागरिकों से आतंकवादी समूहों के खिलाफ लड़ाई में सेना के साथ खड़े होने का आग्रह करने के कुछ दिनों बाद आई है, जिसमें उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि व्यापक जन समर्थन के बिना सशस्त्र बल अकेले आतंकवाद को खत्म नहीं कर सकते। फजलुर रहमान ने अपील की सिरे से खारिज कर दिया और तर्क दिया कि देश की रक्षा करना सेना का संवैधानिक दायित्व है। नागरिकों से राज्य की लड़ाई लड़ने के लिए नहीं कहा जाना चाहिए।

वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका और ईरान के बीच रविवार को तनाव और बढ़ गया, जब अमेरिकी सेना ने होर्मुज स्ट्रेट के आस-पास ईरान के सैन्य ठिकानों पर नए हमले किए। ये हमले एक-दूसरे पर किए जा रहे हमलों और जवाबी हमलों के सिलसिले का ही हिस्सा थे, क्योंकि ईरान इस जलमार्ग से होने वाली शिपिंग पर अपना नियंत्रण जमाना चाहता है। अमेरिकी सेना ने इस रणनीतिक जलमार्ग के आस-पास कई जगहों पर ईरान के मिसाइल सिस्टम, एयर डिफेंस साइट्स और इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) द्वारा चलाई जा रही छोटी स्पीडबोट्स पर हमले किए।

अमेरिकी सेना ने कहा कि उसने ईरान के खिलाफ एक और दौर के हमले किए हैं, ताकि होर्मुज स्ट्रेट से

गुजरने वाले कमर्शियल जहाजों पर हमला करने की उनकी क्षमता को कम किया जा सके। ये हमले ईरान में रात भर और आज सुबह तक जारी रहे। इससे पहले रविवार सुबह सेना ने हमले किए थे, जो एक दिन पहले इस अहम समुद्री रास्ते में एक कंटेनर जहाज पर ईरान के हमले के जवाब में थे। ईरान ने उन हमलों का जवाब खाड़ी के अरब देशों पर हमला करके दिया। हिंसा का यह सिलसिला बढ़ता गया, जिससे तेहरान और वॉशिंगटन के बीच युद्ध खत्म करने की बातचीत टूटने की कगार पर पहुंच गई। अमेरिका ने रविवार को ईरान पर हमला किया। यह हमला होर्मुज स्ट्रेट में एक कंटेनर जहाज पर ईरान के हमले के जवाब में था, जिसमें जहाज में आग लग गई थी और एक क्रू मेंबर लापता हो गया था। ईरान ने बहरीन,

कुवैत, कतर, जॉर्डन और ओमान पर हमले करके जवाब दिया, ये देश स्ट्रेट के दूसरी तरफ हैं और तेहरान ने शिपिंग ट्रैफिक को मैनैज करने में सहयोग के लिए उन पर दबाव डाला था।

अमेरिका ने दिन में बाद में फिर हमला किया। स्ट्रेट के पास स्थित केशम द्वीप के गवर्नर ने ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी IRNA को बताया कि सैन्य ठिकानों पर प्रोजेक्टाइल दागे गए, लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ। तटीय शहर बंदर अब्बास और उत्तर में हाजीआबाद शहर में भी धमाकों की आवाज सुनी गई। अमेरिका के एक अधिकारी ने बताया कि ईरान की कमर्शियल जहाजों पर हमला करने की क्षमता को और कम करने के लिए कुछ जगहों पर मिसाइल और एयर डिफेंस

सिस्टम और पैरामिलिट्री रिवोल्यूशनरी गार्ड की नावों पर हमले किए गए। उन्होंने नाम न बताने की शर्त पर यह बात कही क्योंकि उन्हें मिलिट्री ऑपरेशन्स के बारे में सार्वजनिक रूप से बात करने की इजाजत नहीं थी। ईरान और अमेरिका अपनी उस 60 दिन की अंतर्निम डील के लगभग आधे रास्ते पर हैं, जिसका मकसद युद्ध को हमेशा के लिए खत्म करना है। होर्मुज स्ट्रेट, जो तेल और प्राकृतिक गैस की ग्लोबल सप्लाई के लिए एक अहम रास्ता है और जिसे लंबे समय से एक इंटरनेशनल जलमार्ग माना जाता रहा है, बातचीत में एक अड़चन बन गया है। ऐसी बातचीत जो अब टूटने के कगार पर दिख रही है। एक बयान के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि अगर फिर से बड़े

पैमाने पर लड़ाई शुरू हुई, तो इसके नतीजे बहुत भयानक होंगे। ईरान का कहना है कि होर्मुज स्ट्रेट बंद है, लेकिन अमेरिका इससे सहमत नहीं है। रविवार को अमेरिकी सेना ने बताया कि उसने लगभग 140 ठिकानों पर हमला किया, जिनमें मिसाइल और ड्रोन लॉन्च साइट, गोला-बारूद के भंडार, संचार उपकरण और अन्य ठिकाने शामिल थे।

ये हमले हाल के दिनों की तुलना में ज्यादा जबरदस्त थे। ओमान के पास के रास्ते से गुजरने वाले जहाजों पर हुए हमलों के जवाब में अमेरिका ने पिछले हफ्ते ईरान को निशाना बनाते हुए तीन बार हवाई हमले किए। ये जहाज इस्लामिक रिपब्लिक के समुद्री क्षेत्र से बचने के लिए उस रास्ते का इस्तेमाल कर रहे थे।

'बातचीत की हर कोशिश चाहते थे राष्ट्रपति ट्रंप', पीएम नेतन्याहू ने बताई ईरान पर अमेरिकी नीति क्या?

तेल अवीव, एजेंसी। इस्राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले ईरान के साथ बातचीत के जरिए परमाणु मुद्दे का समाधान निकालना चाहते थे। उनके मुताबिक, ट्रंप की कोशिश थी कि राजनयिक समझौते की सभी संभावनाएं पूरी तरह खत्म होने के बाद ही दूसरे विकल्पों पर विचार किया जाए।

एनबीसी के मीट द प्रेस कार्यक्रम में एक साक्षात्कार के दौरान नेतन्याहू ने जोर देकर कहा कि अगर तेहरान अपनी प्रतिबद्धताओं का उल्लंघन करता है, तो अमेरिकी नेता बल प्रयोग करने में संकोच नहीं करेंगे। नेतन्याहू ने कहा कि मुझे लगता है कि राष्ट्रपति ट्रंप



बातचीत के माध्यम से खास रूप से परमाणु मुद्दे पर समझौते तक पहुंचने

की हर संभव कोशिश करना चाहते हैं। लेकिन जाहिर है, जब ईरान

अपने हर वादे को तोड़ता है, तो वे बल प्रयोग करने से भी नहीं

हिचकिचाते और आमतौर पर वादे करने के कुछ घंटों या कुछ मिनटों के भीतर ही वे ऐसा कर देते हैं। इसलिए, मुझे लगता है कि हमें राष्ट्रपति को अपना मौका देना चाहिए।'

नेतन्याहू ने आभार क्यों व्यक्त किया?

इस्राइल के प्रधानमंत्री ने ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं का मुकाबला करने में अमेरिका-इस्राइल के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। इसके साथ ही कहा कि उनके संयुक्त प्रयासों ने तेहरान को परमाणु हथियार और उन्हें पहुंचाने के साधन हासिल करने से रोक दिया है। उन्होंने कहा, 'आप जानते हैं इस्राइल इस बात के लिए

बेहद आभारी है कि अमेरिका ने ईरान को परमाणु हथियार और उन्हें पहुंचाने के साधन हासिल करने से रोकने के लिए सेना में शामिल हुआ, न केवल हमारे खिलाफ बल्कि पूरे पश्चिम और संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ।'

परमाणु को लेकर क्या बोले नेतन्याहू?

नेतन्याहू ने कहा कि बहुत से लोगों को इस बात का एहसास नहीं है कि ईरान अपनी परमाणु क्षमताओं को बढ़ाने के कितने करीब आ गया था। उन्होंने आगे कहा कि अमेरिका और इस्राइल द्वारा हाल ही में किए गए सैन्य अभियानों ने तेहरान के कार्यक्रम को काफी हद तक पीछे धकेल दिया है।

ऑपरेशन का क्या नाम था? उन्होंने आगे कहा, 'हमने ये दो ऑपरेशन किए, जिन्हें मिडनाइट हैमर और एपिक फ्यूरी कहा जाता है। हम इन्हें राइजिंग लायन और रोरिंग लायन कहते हैं; हमने वास्तव में इसे वापस पटरी पर ला दिया।'

अभी पश्चिम एशिया में क्या हालात?

ये टिप्पणियां अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के मद्देनजर आई हैं। रविवार को, संयुक्त राज्य अमेरिका ने थल और जल आधारित लड़ाकू विमानों, ड्रोनों और नौसैनिक जहाजों द्वारा तैनात स्टायक गोलाबारी का उपयोग करते हुए ईरान के 140 सैन्य ठिकानों पर हमले किए। लक्ष्यों में ईरान के

मिसाइल और ड्रोन ठिकाने, नौसैनिक क्षमताएं, गोला-बारूद भंडारण सुविधाएं, संचार नेटवर्क और तटीय निगरानी स्थल शामिल थे। यह घटनाक्रम होर्मुज जलडमरूमध्य में साइप्रस के ध्वज वाले कंटेनर पोत एम/वी जीएफएस गैलेक्सी पर आईआरजीसी द्वारा किए गए हमले के बाद हुआ। इसके अलावा, सरकारी प्रसारक आईआरआईबी के अनुसार, ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर (आईआरजीसी) ने दावा किया है कि उसने ओमान के दुकूम बंदरगाह पर अमेरिकी विमानवाहक पोते द्वारा उपयोग किए जाने वाले रसद सहायता केंद्री और ईंधन भरने वाले प्लेटफार्मों पर एक भारी और अचानक हमला किया है।



पेपर लीक पर सख्त कार्रवाई की मांग, सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई जनहित याचिका

दिल्ली में महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 2500 रुपये: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता

नई दिल्ली, एजेंसी। पेपर लीक मामले पर सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश देने की मांग की गई है कि वे देश भर में पेपर लीक मामलों की समय-सोमा के भीतर जांच और तेजी से सुनिश्चित करने के लिए एक मानक प्रश्नावली और विशेष जांच प्रक्रिया तैयार करें। अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय की ओर से दायर याचिका में भ्रष्टाचार विरोधी, मनी लॉन्ड्रिंग, बेनामी संपत्ति और काले धन कानूनों के प्रावधानों को लागू करने के अलावा, पेपर लीक के अपराधियों और अपराध में कथित रूप से शामिल उनके परिवार के सदस्यों की चल और अचल संपत्तियों की जब्ती के लिए निर्देश देने की भी मांग की गई है।

याचिका में, जिसमें केंद्र सरकार, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों, साथ ही भारत के विधि आयोग को प्रतिवादी बनाया गया है, यह तर्क



दिया गया है कि बार-बार होने वाले पेपर लीक के देशव्यापी प्रभाव होते हैं, जिससे छात्र और उनके परिवार गंभीर रूप से प्रभावित होते हैं। याचिका में कहा गया है, 'पेपर लीक का देशव्यापी असर हुआ है, जिससे छात्रों और उनके परिवारों पर बुरा असर पड़ा है और कई छात्रों ने आत्महत्या कर ली है।'

याचिका के अनुसार, पेपर लीक के लिए जिम्मेदार लोगों को रोकने, जांच करने और प्रभावी ढंग से मुकदमा चलाने में अधिकारियों की लगातार विफलता के परिणामस्वरूप

बढ़ती आत्महत्याओं का बोझ झेलना पड़ रहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने पारसनाथ डेवलपर्स और उसके निदेशकों के बैंक खाते फ्रीज किए

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पारसनाथ डेवलपर्स और उसके निदेशकों के बैंक खातों को तत्काल प्रभाव से फ्रीज करने का आदेश दिया। साथ ही कंपनी के अधिकारियों के खिलाफ जमानती वारंट जारी किए। अदालत ने वरिष्ठ नागरिकों द्वारा अपने घर का कब्जा पाने के लिए पिछले 20 वर्षों से किए जा रहे संघर्ष का संज्ञान लेते हुए यह सख्त रुख अपनाया। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने नियामक प्राधिकरणों की निष्क्रियता पर गंभीर चिंता जताई। अदालत ने हरियाणा सरकार के तंत्र और बिल्डर के बीच संभावित मिलीभगत की भी

आशंका व्यक्त की। मामला कैसर से उबर चुकीं रीता टिक्कू और लोकेश टिक्कू की ओर से दायर याचिका से संबंधित है। दोनों ने गुरुग्राम के सेक्टर-53 स्थित पारसनाथ एक्सोटीका परियोजना में अपनी जीवनभर की जमा पूंजी निवेश की थी। याचिकाकर्ताओं को वर्ष 2006 में आवासीय इकाइयां आवंटित की गई थीं और वर्ष 2007 की शुरुआत में प्लैट खरीदार समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। करीब 1.78 करोड़ रुपये की पूरी कीमत चुकाने के बावजूद उन्हें वर्ष 2013 तक प्लैट का कब्जा नहीं मिला। दो दशक बीत जाने के बाद भी परियोजना अब तक अधूरी है।

याचिकाकर्ताओं को वर्ष 2021 में हरियाणा रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (एचआरईआरए) से राहत मिली थी, जिसने बिल्डर को मुआवजा देने का आदेश दिया था। हालांकि, बिल्डर ने न तो उस आदेश को चुनौती दी और न ही उसका पालन किया।

प्रशासनिक बाधा न आने पाए।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण केवल एक सामाजिक संकल्प नहीं, बल्कि विकसित भारत की आधारशिला बन चुका है। प्रधानमंत्री ने हमेशा महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को देश की प्रगति का सबसे प्रभावी माध्यम माना है। उसी सोच को आगे बढ़ाते हुए दिल्ली सरकार राजधानी की महिलाओं को 'दिल्ली लक्ष्मी योजना' के माध्यम से आर्थिक रूप से सशक्त, आत्मनिर्भर और सम्मानजनक जीवन जीने का मजबूत आधार उपलब्ध करा रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा विश्वास है कि जब घर की महिला आर्थिक रूप से मजबूत होगी, तब परिवार, समाज और राष्ट्र, तीनों की प्रगति को नई गति मिलेगी। बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि योजना के सभी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए, ताकि इसका लाभ केवल

वास्तविक पात्र लाभार्थियों तक ही पहुंचे। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य योजना को पूरी पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ लागू करना है।

बैठक में योजना की पात्रता संबंधी मानकों पर भी विस्तार से चर्चा हुई। निर्णय के अनुसार योजना का लाभ केवल उसी महिला को मिलेगा, जो स्वयं या उसका परिवार कम से कम 10 वर्षों से दिल्ली की निवासी हो। लाभार्थी व उसके परिवार के विरुद्ध किसी प्रकार का अपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। परिवार में आयु के आधार पर सबसे बड़ी महिला ही इस योजना की पात्र होगी तथा एक परिवार से केवल एक महिला को ही इसका लाभ दिया जाएगा।इसके अलावा लाभार्थी के परिवार की वार्षिक आय ढाई लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। जो महिला पहले से सरकार की किसी पेंशन अथवा अन्य नियमित आर्थिक सहायता योजना का लाभ ले रही है, वह इस योजना के लिए पात्र नहीं होगी।

सिल्क साड़ी में जाह्नवी कपूर ने बिखेरा जलवा, ट्रेडिशनल आउटफिट में लगाया बोल्डनेस का तड़का



साड़ी के साथ जाह्नवी ने मैचिंग स्ट्रेपलेस स्टाइल ब्लाउज कैरी किया है, जो उनके इस एथनिक लुक में मॉडर्न और ग्लैमरस टच जोड़ रहा है।

बॉलीवुड की यंग और खूबसूरत एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर अपने बेहतरीन फैशन सेंस के लिए जानी जाती हैं। हाल ही में उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रही हैं। इन लेटेस्ट तस्वीरों में जाह्नवी का एक अलग ही अंदाज देखने को मिल रहा है, जहां उन्होंने भारतीय परंपरा को बोल्डनेस के साथ पेश किया है। तस्वीरों में जाह्नवी कपूर ने एक बेहद खूबसूरत लैवेंडर और गोल्डन शेड वाली सिल्क साड़ी पहनी हुई है। साड़ी का बॉर्डर काफी हैवी है, जो इसे बेहद रॉयल लुक दे रहा है।

साड़ी के साथ जाह्नवी ने मैचिंग स्ट्रेपलेस स्टाइल ब्लाउज कैरी किया है, जो उनके इस एथनिक लुक में मॉडर्न और ग्लैमरस टच जोड़ रहा है।

तस्वीरों में जाह्नवी एक से बढ़कर एक सेक्सी और अट्रैक्टिव पोज देते नजर आ रही हैं। वह अपना परफेक्ट फिगर फ्लॉन्ट करती दिख रही हैं। उनके इन बोल्ड पोज ने ट्रेडिशनल लुक में भी हॉटनेस का तड़का लगा दिया है।

जाह्नवी ने न्यूड-ग्लॉसी लिपस्टिक, सटल मेकअप, बिग आईलाइनर और माथे पर एक छोटी सी बिंदी के साथ अपने चेहरे की खूबसूरती को निखारा है। इस रॉयल लुक को पूरा करने के लिए जाह्नवी ने अपने बालों का एक नीट और क्लीन स्लीक जूड़ा बनाया हुआ है, जिसे पारंपरिक हैयर एक्सेसरीज से सजाया गया है।

ज्वेलरी की बात करें तो उन्होंने गले में एक बेहद हैवी कुंदन और पलं का चोकर नेकलेस, मैचिंग झुमके, हाथों में ढेर सारी खूबसूरत चूड़ियां, बाजूबंद और अंगुठियां पहनी हुई हैं, जो उनके लुक में चार चांद लगा रहे हैं।



कई प्रोजेक्ट्स टुकराने पर बोलीं अनुपमा की अद्रिजा रॉय, मैं इंतजार करना पसंद करूंगी, लेकिन बिना जुड़ाव के किरदार नहीं

अनुपमा में राही कपाड़िया के किरदार से अभिनेत्री अद्रिजा रॉय ने घर-घर में पहचान बनाई है। अद्रिजा ने कहा कि वह वहीं किरदार निभाना पसंद करती है, जिससे उन्हें दिल से जुड़ाव महसूस होता है। वहीं उन्होंने आगे कहा कि अब महिलाओं के लिए लिखे जाने वाले किरदारों में काफी सुधार आया है और दर्शक भी महिला कर्तृत्व कहानियों को खुले दिल से स्वीकार कर रहे हैं। अद्रिजा रॉय ने कहा, मुझे लगता है कि चीजें पहले से काफी बेहतर हुई हैं। अब महिलाओं को ज्यादा अहमियत रखने वाले किरदार मिल रहे हैं। हालांकि अभी भी सुधार की गुंजाइश है, लेकिन अच्छी बात यह है कि दर्शक अब महिलाओं के नेतृत्व वाली कहानियों को स्वीकार कर रहे हैं। यह इंडस्ट्री के लिए एक सकारात्मक संकेत है। उन्होंने कहा कि ऐसा होना स्वाभाविक है, क्योंकि जब कोई किरदार लोकप्रिय हो जाता है तो लोग उसी तरह के रोल में कलाकार को देखने लगते हैं।

उन्होंने कहा, जब कोई भूमिका लोकप्रिय हो जाती है तो लोग आपको उसी अंदाज में देखने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि आपने उस किरदार को अच्छी तरह निभाया है। मैं इसके लिए किसी को दोष नहीं देती। लेकिन एक कलाकार के तौर पर मैं हमेशा खुद को और दर्शकों को



सम्राज्ञ बनना चाहती हूं। मैं एक ही तरह के किरदार बार-बार नहीं करना चाहती। मेरे लिए हर नया रोल कुछ नया सीखने का मौका होना चाहिए।

अद्रिजा ने अपने करियर के फैसलों को लेकर भी बात की। उन्होंने कहा, हर अभिनेता चाहता है कि उसके पास चुनने के लिए बहुत सारे विकल्प हों, लेकिन यह इंडस्ट्री हमेशा इस तरह काम नहीं करती। कई बार कोई अच्छा प्रोडक्शन हाउस आपको ऐसा किरदार देता है, जो शायद आपकी पहली पसंद न हो। ऐसे में पूरी तस्वीर देखनी चाहिए। कहानी क्या है, टीम कैसी है और किरदार शो में क्या योगदान दे रहा है, इन सभी चीजों को समझना जरूरी होता है। हर स्थिति में कोई एक

सही या गलत जवाब नहीं होता। हर कलाकार को अपने हिसाब से फैसला लेना पड़ता है।

बातचीत के दौरान अद्रिजा ने खुलासा किया कि उन्होंने अपने करियर में कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स को मना किया है, जिनसे वह खुद को जोड़ नहीं पाईं।

उन्होंने कहा, हां, मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए मना किया है। ऐसा इसलिए नहीं था कि वे खराब थे, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं उन किरदारों से जुड़ाव महसूस नहीं कर पाईं। अगर मैं किसी भूमिका पर विश्वास नहीं करती हूं, तो मेरे लिए उसके साथ न्याय करना मुश्किल हो जाता है। मैं इंतजार करना पसंद करूंगी, लेकिन ऐसा काम करना चाहती हूं जो मुझे अंदर से उत्साहित करे।

थलापति विजय की जन नायकन को सेंसर बोर्ड से मिला ए सर्टिफिकेट, रिलीज डेट भी कंफर्म

मिल एक्टर थलापति विजय इन दिनों फिल्म जन नायकन की रिलीज को लेकर चर्चा में हैं। हालांकि, तमिलनाडु के सीएम विजय जोसेफ पिछले 7 महीनों से ही अपनी अपकमिंग फिल्म की रिलीज की वजह से सुर्खियों में रहे हैं। मूवी सेंसर बोर्ड में अटक की हुई थी। इसे पहले जनवरी, 2026 में रिलीज किया जाना था, लेकिन इसे सर्टिफिकेशन बोर्ड से हरी झंडी नहीं मिल पाई थी, जिसके बाद अब फैस का ये 7 महीनों का इंतजार खत्म हो गया है।

तमिलनाडु सीएम थलापति विजय सीएम बनने से पहले अपनी आखिरी फिल्म के तौर पर वो अपने फैस को इस फिल्म को एक गिफ्ट के तौर पर सौंपना चाहते थे लेकिन उनका ये सपना पूरा नहीं हो पाया लेकिन सीएम बनने के बाद अब उनकी इस फिल्म को रिलीज किया जाएगा। फिल्म को सेंसर बोर्ड से हरी झंडी मिली और इसकी रिलीज डेट भी तय हो गई है।

थलापति विजय की फिल्म को ए सर्टिफिकेट दिया गया है, जिसके बाद अब इसे दर्शक अगर फैमिली और बच्चों के साथ देखने का प्लान कर रहे हैं तो वो इसे नहीं दे पाएंगे। फिल्म को ए सर्टिफिकेशन मिलने की वजह से इसे केवल 18 साल की उम्र से ज्यादा के बच्चे ही थिएटर में देख पाएंगे।

गौरतलब है कि सीएम विजय जोसेफ की फिल्म जन नायकन के सर्टिफिकेशन की लड़ाई कोर्ट तक में चली थी। मेकर्स ने पूरे विवाद को लेकर मद्रास हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जहां पर सिंगल जज की बेंच ने फिल्म को तुरंत यू/ए 16+ सर्टिफिकेट देने की घोषणा की थी। हालांकि बाद में इस फैसले को भी बदल दिया गया था। फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था। मेकर्स ने फिल्म पर लगी रोक को हटाने की अपील की थी। सुप्रीम कोर्ट ने



मद्रास हाई कोर्ट को इस मसले को जल्द सुलझाने का आदेश दिया था।

इतना ही नहीं, विजय की फिल्म जन नायकन के ऑनलाइन लोक का भी मामला सामने आ चुका है। करीब 112 करोड़ लोगों द्वारा इसे गैरकानूनी ढंग से डाउनलोड किया था। इसका फेक सेंसर सर्टिफिकेट भी सामने आया था। हालांकि, जब विजय ने सीएम पद की शपथ ली तो उस समय कयास लगाए गए कि अब इसकी रिलीज देरी नहीं होगी और अब इस फिल्म रिलीज का समय भी आ गया।

जन नायकन की रिलीज की बात की जाए तो फिल्म की रिलीज डेट भी कंफर्म हो चुकी है। कनाडा के डिस्ट्रीब्यूटर यॉक सिनेमाज ने बुधवार को एक्स (पहले दिव्बर) पर एक पोस्ट शेयर करते हुए फिल्म की रिलीज डेट का खुलासा किया था। इसमें जानकारी दी गई थी कि इसे 24 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। आपको बता दें कि इस फिल्म में विजय के साथ एक्ट्रेस पूजा हेगड़े लीड रोल में हैं।

